

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व विभाग

देहरादून: दिनांक: 21 सितम्बर 2006

विषय:- मै0 प्रकृति एण्ड कम्पनी को ग्राम चौखुटा पट्टी पूर्वी आगर तहसील धारी में
रिसोर्ट्स/होटल व्यवसाय हेतु कुल 0.100 है0 भूमि कय करने की अनुमति
प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2077/ज्येड0ए0सी0/06 दिनांक 28
अगस्त, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय
मै0 प्रकृति एण्ड कम्पनी को रिसोर्ट्स/ होटल व्यवसाय हेतु उत्तरांचल (उ0प्र0 जर्गीदारी
विन्यास एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001)
(संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(ii) के
अन्तर्गत तहसील धारी के ग्राम चौखुटा पट्टी पूर्वी आगर में कुल 0.100 है0 भूमि कय
करने की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

- 1- कंटा धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा
भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की
अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।
- 2- कंटा बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक
या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने
वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।
- 3- कंटा द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी
गणना भूमि के विक्रय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद
ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में
अभिलिखित किया जायेगा, उसी प्रयोजन के लिये करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान
की गई है। यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे
स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस
प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विक्रय, उपहार या अन्यथा
भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो
जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

- 4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।
- 5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।
- 6- आवेदक स्थापित किये जाने वाले रिसोर्ट्स/होटल व्यवसाय में उत्तरांचल के निवासियों को 70 प्रतिशत रोजगार/सेवायोजन उपलब्ध करायेगा।
- 7- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

(एन0एस0नपलच्यल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- आयुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 3- प्रमुख सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 4- निदेशक, पर्यटन निदेशालय, पटेल नगर, देहरादून।
- 5- श्री शैलेन रूपारेल, डायरेक्टर, मै0 प्रकृति एण्ड कम्पनी, नि0- ए/04
सेक्टर-30, नोएडा उ0प्र0।
- 6- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तरांचल सचिवालय।
- 7- गार्ड फाईल।

आज्ञा रो,
(सुनील सिंह)
अगुसचिव।